{ खुद के लिए जीने वाले की ओर कोई ध्यान नहीं देता पर जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं तो वे आपके लिए जीते हैं - परमहंस योगानंद }

सम्पादकीय

हिंदी विरोध की राजनीति

सिद्ध होती भाषा की उपयोगिता

तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध यही बताता है कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से किस तरह भाषा को हथियार बनाया जा रहा है। त्रिभाषा फार्मूले के तहत मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी को पढ़ाए जाने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय पर सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने आपत्ति उठाई। यह वही राज ठाकरे हैं, जिनके कार्यकर्ता उत्तर भारतीयों पर हमले करने के लिए कुख्यात हैं।

इस पर हैरानी नहीं कि उद्धव ठाकरे भी राज ठाकरे के सुर में सुर मिला रहे हैं। उनकी शिवसेना ने एक समय दक्षिण भारतीयों को मुंबई से भगाने का अभियान छेड़ा था, फिर उसके निशाने पर उत्तर भारतीय आ गए थे। हैरानी इस बात की है कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता भी त्रिभाषा फार्मूले के तहत हिंदी पढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं और इसके पीछे साजिश देख रहे हैं।

अच्छा होता कि मराठी अस्मिता की रक्षा के बहाने हिंदी को निशाने पर ले रहे ये नेता यह बताते कि तीसरी भाषा के रूप में हिंदी के स्थान पर किस भाषा को पढ़ाया जाना चाहिए? तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का चयन इसलिए सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि एक तो वह आधिकारिक राजभाषा एवं सबसे प्रभावी संपर्क भाषा है और दूसरे, महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में हिंदी बोलने-समझने वाले हैं। ये वे लोग हैं, जो काम-धंधे के सिलसिले में महाराष्ट्र गए और फिर वहीं बस गए। इन्होंने महाराष्ट्र के विकास में योगदान भी दिया है। इसकी अनदेखी करते हुए हिंदी का विरोध करना एक तरह का नस्लवाद ही है।

दुनिया में जहां कहीं भी लोग अन्यत्र जाकर बसते हैं, वे अपने साथ अपनी संस्कृति और भाषा भी ले जाते हैं। यदि कोई यह चाहता है कि ऐसा न हो तो ऐसा होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र और अन्य गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी की स्वीकार्यता इसलिए बढ़ रही है, क्योंकि उसकी उपयोगिता सिद्ध हो रही है। हिंदी का मराठी या अन्य किसी भाषा से कोई झगड़ा नहीं। क्या यह विचित्र नहीं कि हिंदी का विरोध उस महाराष्ट्र में हो रहा है, जिसकी राजधानी हिंदी फिल्म उद्योग का गढ़ है?

हिंदी फिल्म उद्योग ने मुंबई को न केवल प्रतिष्ठित किया है, बल्कि महाराष्ट्र के लोगों को लाभान्वित भी किया है। क्या राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आदि हिंदी फिल्म उद्योग का भी विरोध करेंगे? ऐसा करके वे अपने राज्य के लोगों के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का ही काम करेंगे। यह किसी से छिपा नहीं कि हिंदी विरोध के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काने का काम अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए किया जाता है। यह और कुछ नहीं, राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने और लोगों में वैमनस्य पैदा करने वाली क्षुद्र राजनीति है। यह राजनीति प्राय: नाकाम नेता ही अधिक करते हैं।

वि शे ष

वक्फ कानून पर विभाजनकारी राजनीति मुर्शिदाबाद हिंसा की कल्पना नहीं थी

आम तौर पर वक्फ संशोधन कानून का विरोध या तो वे मुस्लिम नेता और संगठन कर रहे हैं जो वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग करते थे या फिर वे राजनीतिक दल जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं और वह भी उन्हें बरगलाकर और डराकर। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों में वक्फ कानून के बहाने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चमकाने की होड़ लगी है।

■ संजय गुप्त

संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने और उसके कानून बनने के उपरांत पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भयावह हिंसा के चलते वहां से सैकड़ों हिंदुओं का पलायन बहुत ही शर्मनाक और चिंताजनक है। इसकी तो आशंका थी कि कुछ मुस्लिम संगठन और राजनीतिक दल इस कानून के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करेंगे, पर मुर्शिदाबाद सरीखी हिंदू विरोधी हिंसा की कल्पना नहीं थी। यह हिंसा बंगाल सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करती है। मुर्शिदाबाद में दो हिंदुओं की घर से खींचकर हत्या भी की गई और बड़े पैमाने पर लूटपाट और आगजनी भी। इसके कारण ही सैकड़ों लोग पलायन करके मालदा और झारखंड भागने को विवश हुए। पता नहीं ये लोग अपने घरों को लौट सकेंगे या नहीं? यदि लौटते हैं तो अपने आपको सुरक्षित महसूस करेंगे या नहीं? वक्फ कानून विरोधियों के उपद्रव को रोकने की कोई कोशिश करने के बजाय बंगाल सरकार जिस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही, उसे तृणमूल कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की विभाजनकारी राजनीति ही कहा जाएगा।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा से किस तरह मुंह मोड़ा, इसका पता इससे चलता है कि हिंसा के लिए उन्होंने विश?व हिंदू परिषद और सीमा सुरक्षा बल को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी दोष मढ़ा। उनकी मानें तो यह हिंसा बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिए की गई। हिंसा के कारण जिन लोगों को पलायन करना पड़ा, उनसे ममता बनर्जी ने लेशमात्र भी सहानुभूति नहीं दिखाई। इसका पता इससे भी चलता है कि उन्होंने राज्यपाल से कहा कि वह पीड़ितों से मिलने मालदा न जाएं। वह उनके आग्रह की अनदेखी कर वहां गए और उन्होंने राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया, लेकिन अभी यह भरोसा नहीं कि हिंसा पीड़ितों को न्याय मिलेगा। वक्फ कानून के विरोध की आड़ में मुर्शिदाबाद और कुछ अन्य स्थानों में की गई हिंसा की सघन जांच जरूरी है। इस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को कठोर दंड का भागीदार बनाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हिंसा पीड़ितों को पूरी राहत भी दी जानी चाहिए।

आखिर वक्फ बिल में ऐसा क्या है कि उसके विरोध के नाम पर हिंसा का सहारा लिया गया और अब भी हिंसा फैलाने की धमकियां दी जा रही हैं? क्या यह किसी से छिपा है कि पुराने वक्फ कानून का विरोध अनेक मुस्लिम संगठन ही कर रहे थे? वे ऐसा इसलिए कर रहे थे, क्योंकि वक्फ बोर्डों की मनमानी से अनेक मुस्लिम भी पीड़ित थे। इन वक्फ बोर्डों से मुसलमानों का कोई भला भी नहीं हो रहा था। आज ऐसे मुस्लिमों को खोजना कठिन है, जिन्हें वक्फ बोर्डों से किसी तरह की सहायता मिली हो। इसके तमाम उदाहरण अवश्य हैं कि वक्फ बोर्ड पदाधिकारियों ने वक्फ संपत्ति बिल्डरों को बेच दी या फिर उसे मामूली किराए पर दे दिया। क्या इससे कोई इन्कार कर सकता है कि वक्फ संपत्तियों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है?

इसी दुरुपयोग के कारण पिछले दिनों बोहरा मुसलमानों के

एक संगठन ने प्रधानमंत्री से मिलकर वक्फ कानून में संशोधन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इसके अलावा कई अन्य मुस्लिम समूहों ने वक्फ संशोधन कानून की प्रशंसा की। केरल के ईसाई संगठनों ने भी इस कानून को सराहा है। वक्फ कानून के विरोधी इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि वक्फ बोर्ड किस तरह गांव के गांव की जमीन पर दावा कर दिया करते थे। इसका जिक्र ससंद में भी किया गया और उच्चतम न्यायालय में भी। यह भी किसी से छिपा नहीं कि अभी हाल में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गुजरात, बिहार आदि में वक्फ बोर्डों के मनमाने दावों से परेशान लोग खुद को वक्फ बोर्डों से बचाने की गुहार लगाते हुए सामने आए। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में बहस के दौरान ऐसे आंकड़े दिए गए थे कि वक्फ कानून में 2013 में किए गए बदलाव के बाद किस तरह वक्फ संपत्ति में अनाप-शनाप वृद्धि दर्ज की गई।

आम तौर पर वक्फ संशोधन कानून का विरोध या तो वे मुस्लिम नेता और संगठन कर रहे हैं, जो वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग करते थे या फिर वे राजनीतिक दल, जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं और वह भी उन्हें बरगलाकर और डराकर। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों में वक्फ कानून के बहाने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चमकाने की होड़ लगी है। वे इस झूठ के सहारे मुसलमानों को बरगलाने के साथ उकसा रहे हैं कि नया वक्फ कानून उनकी मस्जिदें और कब्रिस्तान छीनने का काम करेगा। नए वक्फ कानून में कमियां निकालने की होड़ में उसे संविधान विरोधी, मुस्लिम विरोधी वगैरह तो बताया जा रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है कि संविधान विरोधी तो 1995 और 2013 का वक्फ कानून था। वक्फ कानून आजादी के बाद 1954 में ही बन गया था। समय-समय पर उसमें बदलाव कर वक्फ बोर्डों के अधिकार बढ़ाए गए, लेकिन उनकी संपत्तियों के दुरुपयोग के चलते मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है कि वक्फ बोर्डों के पास अरबों रुपये की जमीन होते हुए भी मुस्लिम समुदाय में गरीबी और अशिक्षा सबसे अधिक है? मुसलमानों को यह समझने की जरुरत है कि कथित मुस्लिम हितैषी राजनीतिक दल उनके वोट हासिल करने के लिए उनका भला करने के स्थान पर उनका तुष्टीकरण कर रहे हैं। उन्हें यह भी समझना होगा कि किसमें उनकी भलाई है और किसमें नहीं?

यदि मुसलमान भाजपा को सिर्फ एक हिंदूवादी दल के रुप में देख कर अपने हित के लिए उठाए गए कदमों की अनदेखी करेंगे तो अपना नुकसान ही करेंगे। क्या वे इसकी अनदेखी कर सकते हैं कि तीन तलाक विरोधी कानून मुस्लिम महिलाओं की भलाई के लिए लाया गया था और इससे उनका सचमुच भला हुआ भी? कोई भी कानून पूर्णतया सही नहीं होता। यदि संशोधित वक्फ कानून में कोई खामी होगी तो उसे उच्चतम न्यायालय दूर कर देगा। मुसलमानों को न केवल उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, बल्कि वक्फ बोर्डों के कामकाज पर निगरानी भी बढ़ानी चाहिए, ताकि वक्फ संपत्तियों का सदुपयपोग हो और गरीब मुसलमानों का भला हो। उन्हें वक्फ कानून पर विभाजनकारी राजनीति करने वालों से सतर्क भी रहना होगा।

(लेखक दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हैं)

देश/प्रदेश

ऑल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन का शिक्षण शिविर सम्पन्न

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर

रिजर्व बैंक वर्कर्स यूनियन, जयपुर यूनिट के अध्यक्ष, एसके शर्मा की ओर से 18-19 अप्रेल को होटल वेस्टा मौर्या पैलेस, एमआई रोड, जयपुर में भारतीय रिजर्व बैंक प्रशासन एवं ऑल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि केंद्रीय कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन), आचार्य सागर विकास, मुख्य अतिथि, जयपुर कार्यालय के उप महाप्रबंधक, लाल सिंह, ऑल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष एसबी कर्माकर एवं महासचिव, रमेश पितले तथा जयपुर वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष, एसके शर्मा ने दीप प्रज्ज्वलित कर शिविर का विधिवत शुभारंभ किया।

यूनियन अध्यक्ष, शर्मा ने बताया कि उद्घाटन सत्र में मुख्य व विशिष्ट अतिथियों के अलावा प्रबंधक (कार्मिक), यूनाइटेड फोरम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉईज के चारों संगठनों के मुख्य पदाधिकारी, रिजर्व बैंक के देश भर के सभी केंद्रों की वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष व सचिव तथा मुंबई व जयपुर यूनिट के लगभग 150 प्रतिभागियों ने सहभागिता निभाई। ऑल इंडिया फेडरेसन के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के साथ अन्य आगंतुक अतिथियों का राजस्थानी साफे, शॉल, श्रीफल एवं बुके देकर स्वागत व अभिनंदन किया तथा स्थानीय यूनिट ने केन्द्रीय यूनिट के पदाधिकारियों का राजस्थानी लहरिया साफा व बुके देकर स्वागत किया। यूनियन अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि शिविर के विशिष्ट अतिथि ने शिविर के महत्व तथा बैंक की कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए सभी कर्मचारियों को 12वें शानदार वेतन समझौते की बधाई देते हुए उनसे बेहतर कार्य-व्यवहार की अपील की तथा प्रशासन द्वारा कर्मचारी हित के और निर्णय लेने बाबत आश्वस्त किया।

मुख्य अतिथि ने भी जयपुर कार्यालय में कर्मचारियों के हित में किए जाने वाले शिविरों व कार्यशालाओं का जिक्र करते हुए इस शिविर के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। तदुपरांत ऑल इंडिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेसन के अध्यक्ष, एसबी कर्माकर व महासचिव रमेश पितले ने शिविर के बारे में विस्तार से बताया तथा 12वें शानदार वेतन समझौते के लिए सभी साथियों को बधाई प्रेषित की। साथ ही आगंतुक मेहमानों का धन्यवाद किया गया।

राजस्थानी फिल्म 'पॉइंट जीरो' और 'मर्दानी' का पोस्टर लॉन्च

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। पारस देवी प्रोडक्शन एवं सनमित प्रोडक्शन राजस्थानी भाषा को उसका वापस गर्व दिलाने को लेकर को दो मेगा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और दोनों फिल्में जिनमें पॉइंट जीरो शूटिंग पूर्ण हो चुकी है एवं मर्दानी जिसका रविवार को मुहूर्त किया गया है। दोनों फिल्मों का पोस्टर लॉन्च रविवार को एक भव्य

समारोह में होटल आंगन जयपुर में किया गया। दोनों फिल्मों की निर्मात्री ममता जैन है एवं दोनों फिल्मों में अभिनेत्री इशिका जैन मुख्य भूमिका में है। उल्लेखनीय है कि पाइंट जीरो जहां देशभक्ति से परिपूर्ण है इसके लेखक निर्देशक क्षितिज कुमार है। वही मर्दानी नारी सशक्तिकरण को नई ऊंचाइयां देगी। यह फिल्म एक्शन से भरपूर है जिनका लेखन निर्देशन लखविंदर सिंह कर रहे हैं पॉइंट जीरो एवं मर्दानी दोनों ही 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'केंद्र की सरकार राजनीतिक द्वेष के कारण कर रही अपनी शक्तियों का दुरुपयोग'

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर

केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा अन्याय पूर्ण तथा मनमाने तरीके से ऐतिहासिक नेशनल हेराल्ड की सम्पत्ति को जप्त करने की कार्यवाही तथा कांग्रेस नेतृत्व के विरुद्ध ईडी द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनायें चार्ज शीट प्रस्तुत करने पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव गिरिराज खंडेलवाल ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार राजनीतिक द्वेष के कारण अपनी शक्तियों का दुरूपयोग कर सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिये यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गाँधी विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के विरूद्ध मनमाने तरीके से कार्यवाही करते हुये ईडी द्वारा चार्ज शीट पेश की गई है जो केवल मात्र राजनीतिक प्रतिशोध के कारण केन्द्र सरकार के ईशारे पर की गई कार्यवाही है उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को मनमाने ढंग से और अन्यायपूर्ण तरीके से जब्त करना और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना। यह कानूनी प्रक्रिया का मामला नहीं है; यह कानून के शासन के रूप में एक राज्य प्रायोजित अपराध है।

श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ हाल ही में आरोप पत्र दाखिल करना राज्य की शक्ति का एक भयावह दुरुपयोग दर्शाता है। यह लोकतांत्रिक विपक्ष के विचार पर सीधा हमला है, सत्तारूढ़ शासन द्वारा राजनीतिक धमकी का एक भद्दा प्रयास है जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। यह बदले की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व कभी चुप नहीं रहेगा। हमने पहले भी भारत की आत्मा के लिए लड़ाई लड़ी है और हम इसे फिर से करेंगे। सत्य, न्याय और संवैधानिक लोकतंत्र के मूल्य हमारे लिए अपरिहार्य हैं। सत्यमेव जयते सिर्फ एक नारा नहीं है-यह एक दृढ़ विश्वास है।

एसएस जैन सुबोध गर्ल्स कॉलेज हर्षिता को स्वयंसेवक का सम्मान

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर

एसएस जैन सुबोध गर्ल्स पीजी कॉलेज सांगानेर की हर्षिता शर्मा को जयपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक (2021-22) पुरस्कारों के लिए सम्मानित किया गया है। एसएस जैन सुबोध गर्ल्स पीजी कॉलेज सांगानेर की प्राचार्या डॉ रीटा जैन ने बताया कि यह उपलब्धि हासिल करने वाला जयपुर जिले का एकमात्र कॉलेज है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत महाविद्यालय, कार्यक्रम अधिकारी रेणु बाला शर्मा, मोनिका पुण्डीर तथा स्वयं सेविकाओं द्वारा वर्ष पर्यंत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम, पक्षियों के लिए दाना पानी, जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक सड़क सुरक्षा, अतिथि व्याख्यान, नि:शुल्क रक्तदान शिविर, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं नेत्र जांच शिविर छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु

प्रशिक्षण साक्षात्कार तथा प्लेसमेंट का आयोजन, कौशल प्रशिक्षण, गोद लिए गांव बुधसिंहपुरा एवं खोखावास में बेरोजगारों तथा निरक्षर व्यक्तियों का सर्वे, प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता मिशन, मतदाता जागरुकता कार्यक्रम कैंसर जागरुकता कार्यक्रम, हर घर तिरंगा वितरण, विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस का आयोजन महाविद्यालय के उत्कृष्ट कार्यों में सम्मिलित है।

परिंदों के लिए लगाए परिंडे

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। मानव समाज सेवा संस्थान राजस्थान एवं रोशनी द्वारा चांदनी चौक स्थित ब्रिजनिधि मंदिर एवम परियों के बाग में परिंदों के लिए परिंडे लगाए।

संस्थान के अध्यक्ष डॉ मुकेश गुप्ता ने बताया कि 'परिंदों के लिए

परिंडे लगाओ अभियान' में रोजाना परिंडे लगाए जा रहे हैं इसी क्रम में रविवार को सुबह चांदनी चौक स्थित ब्रिजनिधि मंदिर एवम आमेर स्थित परिओं के बाग में परिण्डे बांधे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में डॉ. सुनील ढंड, विपिन गुप्ता एवम गौरव बंसल ने परिंडों में नियमित जल व चुग्गा रखने की जिम्मेदारी ली।